NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 23-07-2025

विषय सूची

» अमेरिका का यूनेस्को से बाहर निकलने का निर्णय
» छात्रों में आत्महत्या के मामले
» भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग और सीवर से होने वाली मृत्युएँ
» भारत में विगत पांच वर्षों में IP फाइलिंग में वृद्धि
» RBI का वित्तीय समावेशन सूचकांक
» भारत में समुत्थानशील (Resilient) और समृद्ध शहरों की ओर: विश्व बैंक की रिपोर्ट

संक्षिप्त समाचार

» ग्रेट रुआहा नदी
» महादेई नदी
» राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान(NIRD&PR))
» सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना
» विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट /शीतकालीन कोहरा प्रयोग (WiFEX)
» राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन
» भारतीय वायु सेना द्वारा मिग-21 जेट विमानों को सेवानिवृत्ति प्रदान
» केरल के रबर बागानों के लिए बीटल-फफूंद का खतरा

अमेरिका का यूनेस्को से बाहर निकलने का निर्णय

समाचार में

- संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक और शैक्षिक संस्था *यूनेस्को* से बाहर निकलने का निर्णय लिया है।

अमेरिका द्वारा वापसी के कारण

- कथित रूप से *इज़राइल विरोधी पक्षपात*।
- अमेरिका का कहना है कि यूनेस्को सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों को बढ़ावा देता है जो "अमेरिका फर्स्ट" विदेश नीति के अनुरूप नहीं हैं।
- संगठन में *मौलिक सुधार* की आवश्यकता को लेकर अमेरिका की चिंताएँ बनी हुई हैं।

यूनेस्को से अमेरिका की वापसी के प्रभाव

- **वित्तीय और संरचनात्मक**: अमेरिका एक प्रमुख वित्तीय योगदानकर्ता है, और उसकी वापसी से यूनेस्को के बजट पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे *शिक्षा, संस्कृति और विरासत संरक्षण* कार्यक्रमों की निरंतरता खतरे में पड़ सकती है।
- **वैश्विक विरासत और विज्ञान**: यूनेस्को *विश्व धरोहर स्थलों* की देखरेख करता है, जिनमें अमेरिका के 26 स्थल (जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ग्रैंड कैन्यन आदि) शामिल हैं।
  - इन स्थलों को संरक्षण के लिए मिलने वाली निधि में कटौती हो सकती है और नए स्थलों को सूची में शामिल करने के अवसर भी कम हो सकते हैं।
- **भू-राजनीतिक और कूटनीतिक**: अमेरिका की अनुपस्थिति से अन्य शक्तियों (विशेष रूप से *चीन*) को वैश्विक मानदंडों और प्राथमिकताओं को निर्धारित करने में प्रभाव बढ़ाने का अवसर मिलेगा।
  - इसे *बहुपक्षवाद से पीछे हटने* के रूप में देखा जा सकता है, जिससे अन्य देश भी संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों को कम प्राथमिकता दे सकते हैं।

यूनेस्को के बारे में

- **स्थापना**: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में स्थापित, इसका संविधान 1946 में लागू हुआ।
- **उद्देश्य**: *शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार* में सहयोग के माध्यम से *शांति को बढ़ावा देना*।
- **मुख्यालय**: *पेरिस, फ्रांस*।
- **सदस्य**: जुलाई 2025 तक *194 सदस्य देश* और *12 सहयोगी सदस्य*। अमेरिका ने जुलाई 2023 में पुनः सदस्यता ली।
- **प्रमुख निकाय**: *जनरल कॉन्फ्रेंस* और *कार्यकारी बोर्ड*।
- **महत्वपूर्ण रिपोर्टें**:
  - वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट
  - संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट
  - यूनेस्को विज्ञान रिपोर्ट: 2030 की ओर
  - वैश्विक महासागर विज्ञान रिपोर्ट
- **प्रमुख कार्यक्रम और पहलें**:
  - मानव और जीवमंडल कार्यक्रम (MAB) – 1971
  - अंतरराष्ट्रीय जल विज्ञान कार्यक्रम (IHP)
  - वैश्विक भू-उद्यान नेटवर्क
  - विश्व धरोहर सम्मेलन – 1972
  - यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क (UCCN)

भारत और यूनेस्को

- **परिचय**: भारत *यूनेस्को का संस्थापक सदस्य* है और 1948 से भारत में *दो कार्यालय* हैं।
- **विश्व धरोहर स्थल**: जुलाई 2025 तक भारत में *44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल* हैं (36 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित)।
  - *2025 में नवीनतम जोड़*: भारत के *मराठा सैन्य परिदृश्य* (12 किले)।
- **सांस्कृतिक स्थल उदाहरण**:
  - ताजमहल, अजंता गुफाएँ, एलोरा गुफाएँ, आगरा किला, महाबलीपुरम, कोणार्क सूर्य मंदिर, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स, फतेहपुर सीकरी, हम्पी,

खजुराहो, लाल किला परिसर, कुतुब मीनार, हुमायूँ का मकबरा, जयपुर शहर, धोलावीरा, होयसला के पवित्र समूह, शांतिनिकेतन।

- **प्राकृतिक स्थल उदाहरण**:
  - काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभयारण्य, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी घाट, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान।
- **मिश्रित स्थल**:
  - कंचनजंघा राष्ट्रीय उद्यान।
- **अमूर्त सांस्कृतिक विरासत**: कई भारतीय परंपराएँ यूनेस्को की *अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची* में शामिल हैं:
  - वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा
  - रामलीला
  - कुटियाट्टम
  - छऊ नृत्य
  - राजस्थान के कालबेलिया लोक गीत और नृत्य
  - मुदियेट्टू
  - लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चारण
  - मणिपुर का संकीर्तन
  - जंडियाला गुरु के ठठेरा का पारंपरिक पीतल और तांबे का शिल्प
  - योग
  - कुंभ मेला
  - कोलकाता की दुर्गा पूजा
  - गुजरात का गरबा
- **क्रिएटिव सिटी नेटवर्क**: भारत के कई शहर UCCN का भाग हैं:
  - वाराणसी (संगीत)
  - जयपुर (शिल्प और लोक कला)
  - चेन्नई (संगीत)
  - हैदराबाद (गैस्ट्रोनॉमी)
  - श्रीनगर (शिल्प और लोक कला)
  - ग्वालियर (संगीत)
  - कोझिकोड (साहित्य)
- **जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र**: भारत में *18 जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र* हैं, जिनमें से *12 को MAB कार्यक्रम*

Source: TH

छात्रों में आत्महत्या के मामले

संदर्भ

- हाल ही में, शिक्षा राज्य मंत्री ने संसद में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में भारत में छात्रों की आत्महत्याओं को उजागर किया।

भारत में छात्रों की आत्महत्या

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या रिपोर्ट (ADSI) के अनुसार, 2022 में कुल आत्महत्याओं में से 7.6% छात्र थे, जिनमें से 2,248 आत्महत्याएं प्रत्यक्षतः परीक्षा में असफलता से जुड़ी थीं।
- यह 2021 में 8.0% और 2020 में 8.2% से मामूली गिरावट को दर्शाता है।

छात्र आत्महत्या के लिए उत्तरदायी कारक

- **व्यक्तिगत कमजोरियाँ**: आत्म-सम्मान की कमी, आवेगशीलता, आघात का इतिहास, शारीरिक या यौन शोषण का इतिहास, और सीखने व बौद्धिक अक्षमता।
- **पारिवारिक दबाव**: अत्यधिक चिंतित एवं महत्वाकांक्षी माता-पिता, असामान्य पारिवारिक वातावरण, आलोचना, साथियों से तुलना और परिवार में समर्थन की कमी, शराब की लत, हिंसा, मानसिक और आर्थिक समस्याएं आत्महत्या के जोखिम को बढ़ाती हैं।
- **प्रणालीगत खामियाँ**: एक बिंदु मूल्यांकन प्रणाली, परिणामों को लेकर मीडिया का प्रचार, और करियर मार्गदर्शन की कमी।
- **संस्थानिक तनाव**: शिक्षकों और छात्रों पर 100% पास दर प्राप्त करने का दबाव।

केस स्टडी: कोटा

- भारत की प्रतिस्पर्धी प्रवेश परीक्षाओं के प्रति जुनून ने राजस्थान के कोटा जैसे कोचिंग संस्थानों को जन्म दिया

है, जहां प्रत्येक वर्ष 2 लाख से अधिक छात्र नामांकन करते हैं।

- गहन अध्ययन कार्यक्रम, अलगाव, और मनोरंजन के साधनों की कमी ने 2023 में कोटा में अकेले 29 आत्महत्याओं में योगदान दिया।

नीतिगत पहल और मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप

- **टेली-मनोस कार्यक्रम**: एक राष्ट्रीय टेली-मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन (14416), जिसने 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 42 केंद्रों के माध्यम से 13.6 लाख से अधिक कॉल्स को संभाला है।
- **जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (DMHP)**: स्कूलों में आत्महत्या रोकथाम सेवाएं और जीवन कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- **राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति (NSPS)**: मीडिया संवेदनशीलता, स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ीकरण, और घातक साधनों तक पहुंच को सीमित करके 2030 तक आत्महत्या दर को 10% तक कम करने का लक्ष्य।
- **मनोदर्पण कार्यक्रम**: शिक्षा मंत्रालय की प्रमुख पहल, जो हेल्पलाइन और लाइव सत्रों के माध्यम से मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करती है।
  - यह देश भर में लाखों छात्रों तक पहुंच चुका है।
- **नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान**: युवाओं में बढ़ती लत को पहचानते हुए, केंद्र ने मानसिक स्वास्थ्य समर्थन के साथ-साथ जागरूकता प्रयासों को तेज किया है।
- **यूजीसी परामर्श**: उच्च शिक्षा संस्थानों को शारीरिक फिटनेस, भावनात्मक कल्याण और छात्र कल्याण को प्राथमिकता देने का आग्रह।
- **तनाव प्रबंधन कार्यशालाएं**: IIT-मद्रास, IIT-दिल्ली और IIT-गुवाहाटी जैसे संस्थानों ने मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत लचीलापन निर्माण सत्र शुरू किए हैं।
- **सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप (2025)**: छात्रों के बीच 'आत्महत्या महामारी' घोषित की और लचीले पाठ्यक्रम, सतत मूल्यांकन, एवं परिसर मानसिक स्वास्थ्य समर्थन की सिफारिश की।

आगे की राह

- शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षा आयोग (HECI) की स्थापना के लिए कानून का मसौदा तैयार कर रहा है — एक एकीकृत नियामक निकाय जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में शासन और पारदर्शिता में सुधार करना है।
  - यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप है, जो 'हल्का लेकिन सख्त' नियामक ढांचे की वकालत करता है। वर्तमान में, उच्च शिक्षा की निगरानी खंडित है:
- **UGC**: गैर-तकनीकी शिक्षा
- **AICTE**: तकनीकी संस्थान
- **NCTE**: शिक्षक शिक्षा
- HECI का उद्देश्य इन कार्यों को एकल नियामक के अंतर्गत एकीकृत करना है, जो 2018 के मसौदा विधेयक पर आधारित है जिसमें UGC अधिनियम को निरस्त करने का प्रस्ताव था।

Source: IE

भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग और सीवर से होने वाली मृत्युएँ

संदर्भ

- हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किए गए एक सामाजिक ऑडिट (2022–23) में यह प्रकटीकरण हुआ कि 90% से अधिक सीवर से संबंधित मृत्युएँ बिना सुरक्षा उपकरण या व्यक्तिगत सुरक्षा किट (PPE) के हुईं।

मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या है?

- मैनुअल स्कैवेंजिंग का अर्थ है सूखे शौचालयों, खुले नालों, सीवरों और सेप्टिक टैंकों से मानव मल को हाथों से साफ करना, उठाना और निपटाना।
- यह एक खतरनाक और अपमानजनक पेशा है जो मुख्य रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों को प्रभावित करता है।

भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग क्यों जारी है?

- **विकल्पों की कमी**: शिक्षा और रोजगार के सीमित अवसर लोगों को इस कार्य में बनाए रखते हैं।
- **जाति व्यवस्था**: गहराई से जड़ें जमाए जाति-आधारित भेदभाव कई लोगों को इस पेशे में फंसा देता है।
- **कानून प्रवर्तन की कमजोरी**: मैनुअल स्कैवेंजिंग विरोधी कानूनों का अपर्याप्त कार्यान्वयन।
- **अपर्याप्त स्वच्छता अवसंरचना**: आधुनिक स्वच्छता प्रणालियों की कमी के कारण मैनुअल सफाई की आवश्यकता होती है।
  - शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के पास प्रशिक्षित कर्मियों, यंत्रीकृत उपकरणों और स्वच्छता अवसंरचना को आधुनिक बनाने के लिए धन की कमी होती है।
- **आर्थिक कारण**: सस्ता श्रम मैनुअल स्कैवेंजिंग को वित्तीय रूप से आकर्षक बनाता है।

संवैधानिक और कानूनी आयाम

- **संवैधानिक प्रावधान**:
  - **अनुच्छेद 21**: गरिमा के साथ जीवन का अधिकार सुरक्षित कार्य स्थितियों के अधिकार को शामिल करता है।
  - **अनुच्छेद 23**: जब श्रमिकों को खतरनाक सफाई कार्यों में मजबूर किया जाता है, तो यह जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है।
  - **अनुच्छेद 42**: राज्य को न्यायसंगत और मानवीय कार्य स्थितियाँ सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।
- **कानूनी ढांचा**:
  - **मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013**: मैनुअल स्कैवेंजिंग पर प्रतिबंध लगाता है और प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास को अनिवार्य करता है।
  - **सर्वोच्च न्यायालय (सफाई कर्मचारी आंदोलन बनाम भारत संघ, 2014)**: प्रत्येक सीवर/सेप्टिक टैंक मृत्यु के लिए ₹10 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया और राज्य को उत्तरदायी ठहराया।

मैनुअल स्कैवेंजिंग के विरुद्ध उठाए गए कदम

- **NAMASTE योजना**: सीवर और सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई के कारण होने वाली मृत्युओं को रोकने के प्रयास में राष्ट्रीय यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र कार्य योजना।
- **स्वच्छ भारत अभियान**: स्वच्छता को बढ़ावा देने और मैनुअल स्कैवेंजिंग को कम करने का लक्ष्य।
- **राष्ट्रीय गरिमा अभियान**: मैनुअल स्कैवेंजिंग की अमानवीय प्रथा को समाप्त करने और पूरे भारत में प्रभावित व्यक्तियों के समग्र पुनर्वास को सुनिश्चित करने पर केंद्रित राष्ट्रीय अभियान।
- **बैंडिकूट रोबोट**: भारत का प्रथम स्वदेशी मैनहोल सफाई रोबोट, 2018 में केरल में पेश किया गया। 2023 में, केरल मैनहोल सफाई को पूरी तरह से रोबोटाइज करने वाला प्रथम भारतीय राज्य बना।
- **ILO दिशानिर्देश**: स्वच्छता कर्मियों के लिए गरिमापूर्ण कार्य स्थितियाँ, सुरक्षा, प्रशिक्षण और सामाजिक सुरक्षा की मांग करते हैं।

आगे की राह

- **स्वच्छता कार्य का पूर्ण यंत्रीकरण**: NAMASTE योजना के अंतर्गत सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए आधुनिक मशीनों के उपयोग को अनिवार्य करना, समर्पित फंडिंग और प्रशिक्षण के साथ।
- **शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को सशक्त बनाना**: ULBs को प्रशिक्षित स्टाफ, पर्याप्त धन और उपकरणों से लैस करना ताकि स्वच्छता प्रणालियों को आधुनिक बनाया जा सके और मैनुअल सफाई पर निर्भरता समाप्त की जा सके।
- **स्वच्छता कर्मियों और सीवर से संबंधित मृत्युओं पर वास्तविक समय डेटा बनाए रखना**: पारदर्शिता और नीति प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर ऑडिट और स्वतंत्र निगरानी के साथ।

Source: TH

भारत में विगत पांच वर्षों में IP फाइलिंग में वृद्धि

संदर्भ

- विगत पाँच वर्षों में भारत में बौद्धिक संपदा (IP) फाइलिंग में 44% की वृद्धि हुई है, जो 2020–21 में 4,77,533 से बढ़कर 2024–25 में 6,89,991 हो गई है।

मुख्य निष्कर्ष

- सबसे अधिक वृद्धि भौगोलिक संकेतकों (GI) में 380% देखी गई, इसके बाद डिज़ाइनों में 266%, पेटेंट में 180%, कॉपीराइट में 83%, ट्रेडमार्क में 28%, और सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट-डिज़ाइनों (SICLD) में 20% की वृद्धि हुई।

बौद्धिक संपदा (IP) अधिकार

- बौद्धिक संपदा को सामान्यतः 'मन की उपज' के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- यह एक ऐसी संपत्ति है जो औद्योगिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक क्षेत्रों में बौद्धिक सृजन से उत्पन्न होती है।
- बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) एक कानूनी रूप से लागू होने वाला विशेषाधिकार है जो सीमित अवधि के लिए बौद्धिक संपदा के स्वामी को प्रदान किया जाता है।
- IPR रचनात्मकता और मानवीय प्रयास को पुरस्कृत करता है, जो मानवता की प्रगति को प्रेरित करता है।
- **IPR के प्रकार**
  - पेटेंट
  - कॉपीराइट
  - ट्रेडमार्क
  - औद्योगिक डिज़ाइन
  - भौगोलिक संकेतक
  - इंटीग्रेटेड सर्किट का लेआउट डिज़ाइन
  - पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकारों का संरक्षण
  - अघोषित जानकारी / व्यापार रहस्य का संरक्षण

Form of IPR	What it protects	Criteria	Duration
PATENTS	Inventions	Novelty Inventive Step Industrial Application	20 years from the date of filing the Patent
COPYRIGHTS	Expression of Ideas (Literary, Dramatic, Musical works, Computer Program per se, etc.)	Originality Fixation	Literary works: Lifetime of author + 60 years Cinematography films/records/ photographs/government works : 60 years Broadcasting : 25 years
TRADEMARKS	Identification symbols, logos, slogans, words/ letters	Distinctive Graphically representable Not deceptive	Indefinite Renewal after every ten years
INDUSTRIAL DESIGNS	External appearance of an article	Novel Original Significantly distinguishable	Initially for 10 years Renewal for 5 more years (maximum protection : 15 years)
GEOGRAPHICAL INDICATIONS	Goods of specific geographical origin	Quality Reputation Unique characteristics which are essentially attributable to the geographical area of origin	Indefinite Renewal after every ten years
LAYOUT DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS	Lay out of components in the integrated circuits	Original Distinctive Capable of distinguishing from any other lay-out design.	10 years
PROTECTION OF PLANT VARIETIES & FARMERS' RIGHTS	New varieties Farmers' varieties Extant varieties Essentially derived varieties	Novelty Distinctiveness Uniformity Stability Denomination	Trees and vines : 18 years Extant varieties &others : 15 years

क्या भारतीय पेटेंट अन्य देशों में मान्य होता है?

- नहीं, पेटेंट अधिकार क्षेत्रीय होते हैं, जो केवल उस देश की सीमा में मान्य होते हैं जिसने पेटेंट जारी किया है।
- इसलिए, भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया पेटेंट केवल भारत में ही मान्य होगा।

भारत की पहलें

- **राष्ट्रीय IPR नीति 2016:** सभी IPR को एक एकीकृत दृष्टि दस्तावेज़ में समाहित करती है, जो कार्यान्वयन, निगरानी और समीक्षा के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करती है।
  - यह नीति नवाचार एवं रचनात्मकता को प्रोत्साहित करती है, और आविष्कारकों, कलाकारों व सृजनकर्ताओं को मजबूत संरक्षण व प्रोत्साहन प्रदान करती है।
- **AI और ML आधारित ट्रेडमार्क खोज तकनीक:** ट्रेडमार्क आवेदनों की अधिक कुशल और सटीक जांच तथा तीव्र निपटान के लिए शुरू की गई।
- **स्टार्ट-अप्स बौद्धिक संपदा संरक्षण (SIPP) योजना:** 2016 में शुरू की गई, जो स्टार्टअप्स को पेटेंट, ट्रेडमार्क और डिज़ाइन आवेदन दाखिल करने व प्रक्रिया में नि:शुल्क सहायता प्रदान करती है।
- **बौद्धिक संपदा प्रचार और प्रबंधन प्रकोष्ठ (CIPAM):** राष्ट्रीय IPR नीति के कार्यान्वयन के समन्वय हेतु स्थापित।

- **राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (NIPAM):** शैक्षणिक संस्थानों में IP जागरूकता और मूल प्रशिक्षण प्रदान करने वाला प्रमुख कार्यक्रम।
- **अटल नवाचार मिशन (AIM):** 2016 में NITI आयोग द्वारा शुरू किया गया, जो भारत में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देता है।
  - AIM के चार प्रमुख कार्यक्रम हैं:
- अटल टिंकरिंग लैब्स
- अटल इनक्यूबेशन सेंटर्स
- अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस और अटल ग्रैंड चैलेंजेस
- मेंटर इंडिया

निष्कर्ष

- भारत की IP वृद्धि, विशेष रूप से पेटेंट, औद्योगिक डिज़ाइन और ट्रेडमार्क में उल्लेखनीय प्रगति, नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक आर्थिक उपस्थिति को मजबूत करने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह गति भारत के व्यापक आर्थिक विस्तार एवं नवाचार-आधारित विकास के लक्ष्यों को समर्थन प्रदान करती है।

Source: PIB

RBI का वित्तीय समावेशन सूचकांक

समाचार में

- भारतीय रिज़र्व बैंक का वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI-Index) FY25 में 4.3% बढ़ा।

वित्तीय समावेशन क्या है?

- इसका अर्थ है कि व्यक्ति और व्यवसायों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप, सुलभ और किफायती वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच और उनका उपयोग प्राप्त हो, जो उत्तरदायी और स्थायित्व के साथ प्रदान की जाती हैं।

वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI-Index)

- यह एक व्यापक सूचकांक है जो बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक और पेंशन क्षेत्र की जानकारी को शामिल करता है, जिसे सरकार और संबंधित क्षेत्रीय नियामकों के परामर्श से तैयार किया गया है।
- यह वित्तीय समावेशन के विभिन्न पहलुओं को एक ही मूल्य में समाहित करता है, जो 0 से 100 के बीच होता है, जहाँ 0 पूर्ण वित्तीय बहिष्करण और 100 पूर्ण वित्तीय समावेशन को दर्शाता है।
- यह तीन व्यापक मापदंडों पर आधारित है:
- **पहुँच (Access) – 35% भारांश:** यह दर्शाता है कि वित्तीय सेवाएँ कितनी आसानी से उपलब्ध हैं।
- **उपयोग (Usage) – 45% भारांश:** यह दर्शाता है कि लोग इन सेवाओं का कितनी बार और कितनी प्रभावी रूप से उपयोग कर रहे हैं।
- **गुणवत्ता (Quality) – 20% भारांश:** इसमें वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण, असमानताओं और सेवा की कमियों को कम करने जैसे पहलू शामिल हैं।

हालिया आंकड़ों के प्रमुख निष्कर्ष

- सूचकांक का मूल्य मार्च 2024 में 64.2 से बढ़कर मार्च 2025 में 67 हो गया।
- सभी उप-सूचकांकों – पहुँच, उपयोग और गुणवत्ता – में वृद्धि देखी गई।
- FY25 में सुधार मुख्य रूप से उपयोग और गुणवत्ता आयामों में वृद्धि के कारण हुआ, जो वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के साथ गहरी भागीदारी और वित्तीय साक्षरता प्रयासों के प्रभाव को दर्शाता है।

महत्व

- वित्तीय समावेशन उद्यमिता और व्यवसाय वृद्धि को समर्थन देता है।
- यह 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में से 7 को प्राप्त करने के लिए उत्प्रेरक है।
- यह आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार को बढ़ावा देता है, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करता है और गरीबी उन्मूलन में योगदान देता है।
- यह जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील लोगों और व्यवसायों के लिए लचीलापन निर्माण में सहायता करता है।

- FI-Index में वृद्धि भारत की वित्तीय पहुँच को बढ़ाने और उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में सफलता को दर्शाती है।
- यह सरकार के आर्थिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास के व्यापक एजेंडे को समर्थन देता है, जिससे भारत की औपचारिक वित्तीय प्रणाली को मजबूती मिलती है।

संबंधित पहलें

- प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के अंतर्गत जनवरी 2025 तक 54.58 करोड़ खाते खोले गए, जिनमें ₹2.46 लाख करोड़ की जमा राशि है।
- अटल पेंशन योजना (APY) के अंतर्गत जनवरी 2025 तक 7.33 करोड़ नामांकन हुए, जिनमें FY 2024-25 में 89.95 लाख नए नामांकन शामिल हैं।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के अंतर्गत 22.52 करोड़ लोगों का नामांकन हुआ, और ₹17,600 करोड़ की राशि 8.8 लाख दावों के लिए वितरित की गई।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के अंतर्गत 49.12 करोड़ लोगों को कवर किया गया, और ₹2,994.75 करोड़ की राशि दुर्घटना दावों के लिए वितरित की गई।
- स्टैंड-अप इंडिया योजना के अंतर्गत ₹53,609 करोड़ के ऋण 2.36 लाख उद्यमियों को स्वीकृत किए गए, जिनमें SC/ST और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के अंतर्गत ₹32.36 लाख करोड़ के 51.41 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए, जिनमें 68% ऋण महिलाओं को और 50% SC/ST/OBC वर्गों को दिए गए।

वित्तीय समावेशन की चुनौतियाँ

- उच्च और निम्न आय वाले देशों के बीच खाता स्वामित्व में बड़ा अंतर।
- विकासशील देशों में महिलाएँ वित्तीय सेवाओं तक पहुँच में पीछे हैं।
- अपर्याप्त डिजिटल अवसंरचना और कम डिजिटल साक्षरता मोबाइल वित्तीय सेवाओं की पहुँच में बाधा डालती है।
- कमजोर उपभोक्ता संरक्षण उपयोगकर्ताओं को धोखाधड़ी, दुरुपयोग और पारदर्शिता की कमी के प्रति संवेदनशील बनाता है।

सुझाव और आगे की राह

- भारत सरकार की वित्तीय समावेशन पहलें आर्थिक और सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों को औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक समान पहुँच प्रदान कर सशक्त बनाने की आधारशिला हैं।
- डिजिटल वित्तीय सेवाओं के सुरक्षित एवं निष्पक्ष उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए नियामक ढांचे और उपभोक्ता संरक्षण को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

Source :TH

भारत में समुत्थानशील(Resilient) और समृद्ध शहरों की ओर: विश्व बैंक की रिपोर्ट

समाचार में

- विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट टुवर्ड्स रेसिलिएंट एंड प्रोस्पेरोउस सिटीज इन इंडिया (भारत में समुत्थानशील और समृद्ध शहरों की ओर)।

रिपोर्ट के बारे में

- यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सहयोग से तैयार की गई है।
- इसमें भारत के 24 शहरों का अध्ययन किया गया, जिनमें चेन्नई, इंदौर, नई दिल्ली, लखनऊ, सूरत और तिरुवनंतपुरम पर विशेष ध्यान दिया गया।

हालिया रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- भारतीय शहरों में आर्थिक विकास की अपार संभावनाएँ हैं, 2030 तक 70% नए रोजगार शहरों से आने की संभावना है।
- भारत की शहरी जनसंख्या 2050 तक लगभग दोगुनी होकर 951 मिलियन तक पहुँचने की संभावना है। इससे

2070 तक 144 मिलियन नए घरों की आवश्यकता होगी।

- स्मार्ट निवेश से 2030 तक हर साल $5 बिलियन की बाढ़ क्षति को रोका जा सकता है और 2070 तक यह बचत $30 बिलियन तक पहुँच सकती है।
- साथ ही, 2050 तक अत्यधिक गर्मी से 1,30,000 से अधिक जीवन बचाए जा सकते हैं।

समस्याएँ

- शहरों को अत्यधिक गर्मी और बाढ़ जैसी चरम मौसम की घटनाओं से बढ़ते जोखिम का सामना करना पड़ रहा है।
- शहरों के केंद्रों में बढ़ते तापमान और तीव्र निर्माण के कारण खराब जल निकासी व्यवस्था शहरों को अधिक गर्म एवं बाढ़-प्रवण बना रही है।

सिफारिशें

- अत्यधिक शहरी गर्मी और बाढ़ से निपटने के लिए कार्यक्रम लागू करें, जिनमें बेहतर तूफानी जल प्रबंधन, हरित स्थानों का विस्तार, कूल रूफ की स्थापना और प्रभावी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली शामिल हो।
- लचीले बुनियादी ढांचे और नगरपालिका सेवाओं में निवेश करें, ऊर्जा-कुशल एवं लचीले आवास बनाएं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को आधुनिक बनाएं, तथा शहरी परिवहन को बाढ़-प्रतिरोधी बनाएं।
- निजी क्षेत्र की बेहतर भागीदारी के माध्यम से शहरी वित्त तक पहुँच में सुधार करें।
- 2050 तक शहरों में नए, लचीले और कम-कार्बन बुनियादी ढांचे एवं सेवाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए $2.4 ट्रिलियन से अधिक निवेश की आवश्यकता होगी।
- इन निवेशों को पूरा करने में निजी क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी।

Source :IE

संक्षिप्त समाचार

ग्रेट रुआहा नदी

समाचार में

- तंज़ानिया की *विज़न 2050* योजना जलवायु संकट से जूझ रही ग्रेट रुआहा नदी को बचाने का लक्ष्य रखती है, जो कृषि और जैव विविधता के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है।

ग्रेट रुआहा नदी के बारे में

- यह दक्षिण-मध्य तंज़ानिया की एक प्रमुख नदी है।
- यह उत्तर-पूर्व दिशा में उसांगु वेटलैंड्स से होकर प्रवाहित होती है, फिर उसांगु मैदानों से नीचे उतरती है (जो कृषि और पशुपालन के लिए महत्वपूर्ण हैं), और अंततः रुआहा नेशनल पार्क से होकर गुजरती है।

Source: TH

महादेई नदी

समाचार में

- गोवा कर्नाटक पर महादेई नदी की सहायक नदी कलासा का जल अवैध रूप से मोड़ने का आरोप लगाते हुए सर्वोच्च न्यायालय में ले जा रहा है।

महादेई नदी के बारे में

- **उद्गम:** पश्चिमी घाट (भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, कर्नाटक)
- **बेसिन:** (गोवा 78%, कर्नाटक 18%, महाराष्ट्र 4%)। यह कर्नाटक से होकर गोवा में प्रवाहित होती है, जहाँ इसे मंडोवी के नाम से जाना जाता है, और अरब सागर में गिरती है।

Source: TH

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान(NIRD&PR)

समाचार में

- हाल ही में, संसदीय पैनल ने कुप्रबंधन और पारदर्शिता की कमी का उदाहरण देते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास

एवं पंचायती राज संस्थान (NIRD&PR) के वर्तमान प्रशासन की तत्काल समीक्षा की सिफारिश की है।

NIRD&PR के बारे में

- यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है।
- यह तेलंगाना राज्य के ऐतिहासिक शहर हैदराबाद में स्थित है।
- यह ग्रामीण विकास और पंचायती राज में उत्कृष्टता का एक प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र है।
- इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र-एस्केप उत्कृष्टता केंद्रों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- यह प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं परामर्श की परस्पर संबंधित गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण विकास पदाधिकारियों, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों, बैंकरों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों की क्षमता का निर्माण करता है।
- NIRD&PR ने 2008 में अपनी स्थापना का स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया। हैदराबाद में मुख्य परिसर के अतिरिक्त, इस संस्थान का पूर्वोत्तर क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गुवाहाटी, असम में एक पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केंद्र भी है।

Source: IE

सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना

समाचार में

- केंद्र सरकार सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को लागू करने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रही है।

विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना

- यह एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसका उद्देश्य ग्रामीण कृषि-बुनियादी ढाँचे में क्रांति लाना और देश भर में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को सशक्त बनाना है।
- इसे 2023 में मंज़ूरी मिली थी और वर्तमान में इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जा रहा है।
- यह PACS स्तर पर गोदामों, कस्टम हायरिंग केंद्रों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और उचित मूल्य की दुकानों सहित बुनियादी ढाँचे के निर्माण पर केंद्रित है।
- ये विकास विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे कृषि अवसंरचना कोष (AIF), कृषि विपणन अवसंरचना योजना (AMI), कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन (SMAM), और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण (PMFME) योजना के अभिसरण के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

महत्व

- यह बुनियादी स्तर पर अनाज भंडारण और कृषि रसद में परिवर्तन लाने के लिए तैयार है।
- यह सहकारी क्षेत्र में पारदर्शिता, रिकॉर्ड-कीपिंग और ऋण वितरण में सुधार करके कृषि कार्यों को बढ़ा रहा है।
- महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात एवं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य ईआरपी प्रणाली के अंतर्गत पैक्स को शामिल करने और परिचालन में अग्रणी हैं।

Source :Air

विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट /शीतकालीन कोहरा प्रयोग (WiFEX)

समाचार में

- *विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट (WiFEX)*, जिसे 2015 में शुरू किया गया था, ने उत्तर भारत में घने शीतकालीन कोहरे की गतिशीलता पर दस वर्षों की अग्रणी शोध यात्रा पूरी कर ली है।

परिचय

- **मुख्य उद्देश्य**: उच्च गुणवत्ता वाला प्रेक्षणीय डेटा उत्पन्न करना और एक विश्वसनीय उच्च-रिज़ॉल्यूशन कोहरा पूर्वानुमान मॉडल विकसित करना।
- **नेतृत्व संस्थान**: यह प्रयोग भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM), पुणे द्वारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के तहत संचालित किया गया।

- **कवरेज**: शुरुआत में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGIA) पर केंद्रित रहा; बाद में WiFEX-II के तहत गुवाहाटी और नोएडा के नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (जेवर) सहित उत्तर और पूर्वोत्तर भारत के प्रमुख हवाई अड्डों को शामिल किया गया।

SAFAR से संबंध

- SAFAR (वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान अनुसंधान प्रणाली), जिसे भी IITM द्वारा संचालित किया जाता है, प्रमुख शहरों में व्यापक वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान प्रदान करता है, जो प्रदूषण और मौसम से संबंधित जोखिमों को कम करने की रणनीतियों का समर्थन करता है।

Source: IE

राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन

संदर्भ

- भारत ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत 6 करोड़ जांच का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

मिशन के बारे में

- *राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन* का उद्घाटन 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के शहडोल में किया गया था।
- यह मिशन *राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)* के अंतर्गत मिशन मोड में संचालित किया जा रहा है।
- इसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक भारत से सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करना है।
- इसके लिए जन-जागरूकता, प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में 0–40 वर्ष आयु वर्ग के 7 करोड़ व्यक्तियों की सार्वभौमिक स्क्रीनिंग (वित्त वर्ष 2025–26 तक), और परामर्श सहायता प्रदान की जा रही है।
- सिकल सेल रोग (SCD) की स्क्रीनिंग *प्रमाणित पॉइंट-ऑफ-केयर टेस्टिंग (POCT) किट्स* के माध्यम से की जा रही है, जो तेज़, विश्वसनीय और पुष्टि योग्य परिणाम प्रदान करती हैं।
- इसके अतिरिक्त, सभी भाग लेने वाले राज्यों से स्क्रीनिंग डेटा को समेकित करने के लिए एक *समर्पित डैशबोर्ड* और *सिकल सेल रोग पोर्टल* स्थापित किया गया है।

Source: PIB

भारतीय वायु सेना द्वारा मिग-21 जेट विमानों को सेवानिवृत्ति प्रदान

संदर्भ

- देश की सेवा में छह दशकों से अधिक समय तक सक्रिय रहने के बाद, भारतीय वायु सेना (IAF) सितंबर 2025 में अपने अंतिम *MiG-21 Bison* जेट को सेवानिवृत्त करेगी।

MiG-21 विमान क्या है?

- *MiG-21* या *मिकोयान-गुरेविच मिग-21* एक एकल इंजन वाला, एक सीट वाला सुपरसोनिक जेट फाइटर और ग्राउंड अटैक विमान है, जिसे मूल रूप से 1963 में भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया था।
- यह भारत का प्रथम सुपरसोनिक जेट विमान होने का गौरव रखता है और कई दशकों तक IAF के लड़ाकू बेड़े की रीढ़ बना रहा।
- वर्षों में इसके 700 से अधिक विभिन्न संस्करणों को प्राप्त किया गया, जिनमें से कई को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया।
- यह विमान 1971 के *बांग्लादेश मुक्ति युद्ध* और 1999 के *कारगिल युद्ध* में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है।

Source: TH

केरल के रबर बागानों के लिए बीटल-फफूंद का खतरा

संदर्भ

- केरल में रबर के बागानों को *एम्ब्रोसिया बीटल* (Euplatypus parallelus) और दो कवकों (*फ्यूसेरियम एम्ब्रोसिया और एफ सोलानी*) के बीच *पारस्परिक संबंध* से खतरा उत्पन्न हो रहा है, जिससे वृक्षों को व्यापक हानि हो रही है।

बीटल-कवक पारस्परिकता

- एम्ब्रोसिया बीटल मुख्य रूप से मृत, संक्रमित या तनावग्रस्त वृक्षों पर हमला करते हैं—प्रायः उन वृक्षों से निकलने वाले *इथेनॉल* की गंध से आकर्षित होते हैं।
- ये बीटल लकड़ी को सीधे नहीं खाते; बल्कि वे *गैलरी* नामक सुरंगें छाल में बनाते हैं और उनमें पारस्परिक रूप से जुड़े कवकों (जैसे *फ्यूजेरियम एसपीपी.*) को प्रवेश कराते हैं।
- ये कवक *एंजाइम* छोड़कर लकड़ी के ऊतकों को विघटित करते हैं, जिससे पोषक तत्वों से भरपूर वातावरण बनता है।
- बीटल और उनके लार्वा पेड़ को नहीं, बल्कि *फंगल मायसेलिया* को खाते हैं।

भारत में रबर उत्पादन

- प्राकृतिक रबर *हेविया ब्रासिलिएन्सिस* नामक वृक्ष के *लेटेक्स* से प्राप्त होता है, जो अमेज़न बेसिन में पाया जाता है।
- **केरल:** भारत में रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य है, जो देश के कुल उत्पादन का 70% से अधिक योगदान देता है।
- **अन्य प्रमुख राज्य हैं:** तमिलनाडु, कर्नाटक, त्रिपुरा, और असम।
- भारत *वैश्विक स्तर पर छठा सबसे बड़ा* रबर उत्पादक देश है और *उत्पादकता* के मामले में *दूसरे स्थान* पर है।

Source: TH